6 जनवरी 2026
मंगलवार

केशव टाइम्स
डिजिटल संस्करण

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, विभागीय तालमेल से प्रशासन को और प्रभावी बनाने पर जोर

2

एक नजर

बार काउंसिल चुनाव लड़ने वाले दिव्यांग वकीलों को राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांग वकीलों को राज्य बार काउंसिल के चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए उन्हें फिलहाल विभिन्न समितियों में शामिल कर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग वकीलों के बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाने के लिए एक कानून में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि ऐसे वकीलों से नामांकन शुल्क 1.25 लाख रुपये की जगह 15 हजार रुपये लिया जाए, जो आगामी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं।एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ को बीसीआई के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्तमान कानून के तहत मुख्य काउंसिल में विशेष रूप से सक्षम वकीलों के लिए आरक्षण या समायोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि, उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि बीसीआई उन्हें राज्य बार काउंसिल की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है।

गोवा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका

पणजी। गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर, कार्यवाहक राज्य प्रमुख श्रीकृष्ण परब और तीन अन्य पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देते हुए पार्टी छोड़ दी। इन सामूहिक इस्तीफों को पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर ने एक्स पर लिखा कि मैं आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। यह फैसला मैंने काफी सोच-विचार के बाद और साफ मन से लिया है। पद से अधिक सिद्धांत मायने रखते हैं। सत्ता से अधिक मकसद मायने रखता है। मैं अपने विश्वासों और गोवा के लोगों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। यह सफर जारी रहेगा।पालेकर, श्रीकृष्ण परब और गोवा आम आदमी पार्टी युवा विंग के अध्यक्ष रोहन नाइक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा की।

भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप : रक्षा मंत्री

- 4,200 टन वजनी, 114.5 मीटर लंबे और 22 समुद्री मील प्रति घंटा से ज्यादा गति से चलेगा पोत
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है पोत

एजेंसी। नई दिल्ली

पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पोत भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक रणनीतिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि समुद्री संसाधन किसी एक देश की संपत्ति नहीं हैं, बल्कि मानवता की साझा विरासत हैं। और, जब विरासत साझा होती है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी साझा होती है। यही कारण है कि भारत आज विश्व मंच पर शांति, स्थिरता और पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी के सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़ा है। सोमवार को रक्षा मंत्री ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के दो प्रदूषण नियंत्रण पोतों में से पहले पोत ₹समुद्र प्रताप₹ का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि 4,200 टन वजनी, 114.5 मीटर लंबे और 22 समुद्री मील प्रति घंटा से ज्यादा गति वाले इस पोत के जलावतरण से हमारी ताकत बढ़ेगी और देश का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यह पोत हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतीक है।

आधुनिक अग्निशमन क्षमताओं से लैस है पोत

यह पोत उन्नत प्रदूषण पहचान प्रणालियों, प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष नौकाओं और आधुनिक अग्निशमन क्षमताओं से लैस है। इसमें हेलीकाप्टर हैंगर और विमानन सहायता सुविधाएं भी हैं, जो इसकी पहुंच और प्रभावशीलता को काफी बढ़ा सकती हैं। राजनाथ ने विश्वास व्यक्त किया कि इन क्षमताओं के कारण यह पोत खराब समुद्री परिस्थितियों में भी स्थिर रूप से काम कर सकेगा, जिससे वास्तविक परिचालन में बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि तटरक्षक बल जिस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, उससे देश के शत्रुओं को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि यदि वे भारत की समुद्री सीमाओं पर बुरी नजर डालने या किसी भी प्रकार का दुस्साहस करने का साहस करते हैं, तो उन्हें करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

पहली बार समुद्र प्रताप पर होंगी दो महिला

पहली बार इस पोत पर दो महिला अधिकारी होंगी। रक्षा मंत्री ने सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए तटरक्षक बल की सराहना करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि आज महिला अधिकारियों को पायलट, ऑब्जर्वर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर और लॉ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, साथ ही उन्हें होवरक्राफ्ट संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय रूप से तैनात किया जा रहा है।

अगले चार दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

एजेंसी। नई दिल्ली

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच मौसम लगातार कर-वट बदल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और कोहरे के कारण गलन वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने रविवार को ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की थी। अब ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सकुर्लेशन की वजह से 9 जनवरी तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने सभी से सावधानी बरतने की अपील की है।मौसम विभाग ने बताया कि हाल के दिनों में तमिलनाडु में तापमान में गिरावट आई है। लोकल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। सुबह 8.30 बजे तक इकट्ठा किए गए डेटा के मुताबिक, तिरुनेलवेली जिले के नालुमुक्कू में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सबसे ज्यादा थी। दक्षिण बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सकुर्लेशन की वजह से आने वाले दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में रुक-रुक कर हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ-साथ रात के तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 7 जनवरी तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

अमेरिका आने के बाद ड्रग्स और हथियारों के आरोपों में रखा गया

वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति को पेशी के लिए अदालत में लाया गया

- मादुरो पर पहले भी 2020 में कुछ आरोप लगाए गए थे। अब एक नया अभियोग सामने शुरू किया गया

एजेंसी। नई दिल्ली

वेनजुएला के अपदस्थ नेता निकोलस मादुरो सोमवार को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन पहुंचे, जहां उन्हें अमेरिका में पहली बार अदालत में पेश होना है। यह घटनाक्रम उनकी काराकास में नाटकीय गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद हुआ है। मादुरो (63 वर्षीय) को हेलिकॉप्टर से मैनहट्टन संघीय कोर्ट के पास हेलिपोर्ट लाया गया और वहां से उन्हें बख्तरबंद वाहन में स्थानांतरित किया गया। मादुरो हल्के भूरे रंग की जेल की पोशाक और चमकीले नारंगी जूतों में नजर आए और ड्रग्स कानून लागू करने वाले एजेंट (डीईए) उन्हें सुरक्षा के साथ अदालत ले गए। उन्हें लंगड़ाकर चलते हुए देखा गया। उनके साथ एक महिला भी थीं, जिन्हें उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस बताया जा रहा है और वह भी हिरासत में हैं। इससे पहले मादुरो को एक काफिले में ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन हिरासत केंद्र लाया गया, जहां उन्हें अमेरिका आने के बाद ड्रग्स और हथियारों के आरोपों में रखा गया था। उन्हें आज अदालत में औपचारिक रूप से नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपों का सामना करना है। काराकास में गिरफ्तारी के बाद मादुरो मादुरो को आज न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिका ने एक सैन्य अभियान के जरिये उन्हें हिरासत में लिया है। उन पर नशीली दवाओं की तस्करी और हथियारों के अपराध से जुड़े आरोप हैं। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए एक आपराधिक नेटवर्क का नेतृत्व किया। मादुरो पर चार मुख्य आरोप हैं- नशीली दवाओं और आतंकवाद की साजिश, कोकीन की तस्करी की साजिश, मशीन गन व विनाशकारी हथियार रखने का आरोप और मशीन गन और विनाशकारी हथियार रखने की साजिश। मादुरो पर पहले भी 2020 में कुछ आरोप लगाए गए थे। अब एक नया अभियोग सामने शुरू किया गया है जिसमें और अधिक विवरण जोड़ा गया है और नए लोग आरोपी बनाए गए हैं।

अमेरिकी सीनेटर का दावा- भारत ने रूस से तेल आयात घटाकर टैरिफ हटाने को कहा

अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने टैरिफ प्रकरण पर भारत के बारे में बड़ा दावा किया है। ग्राहम के अनुसार, भारतीय राजदूत विनय कुमार क्वात्रा ने उन्हें कहा है कि भारत रूस के साथ तेल की खरीद घटा रहा है, इसलिए वे टैरिफ घटाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। इसके बाद ग्राहम ने कहा, ₹पके महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर पर था, मैं उनसे जानना चाहा था कि भारत रूस से तेल कैसे खरीद रहा है? ग्राहम के अनुसार भारतीय राजदूत ने उन्हें कहा, ₹क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप से टैरिफ पर ढील देने की बात करेंगे।₹ ग्राहम ने कहा कि ट्रंप की ओर से भारत पर की गई कार्रवाई ही वह मुख्य कारण है जिसके चलते भारत अब काफी कम मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है। गौरतलब है कि पिछले महीने विनय क्वात्रा ने ग्राहम और अन्य अमेरिकी सीनेटरों की 'इंडिया हाउस' में मेजबानी की थी, जहां ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई थी।

अमजेर शरीफ में पीएम मोदी के चादर चढ़ाने पर नहीं लगेगी रोक

एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर औपचारिक रूप से 'चादर' चढ़ाने से रोकने का निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यह मुद्दा तर्कसंगत नहीं है। इस याचिका में केंद्र सरकार और उसके संस्थानों द्वारा इस्लामी विद्वान ख्वाजा मोइनुद्दीन

चिश्ती और अजमेर दरगाह को राज्य प्रायोजित औपचारिक सम्मान और प्रतीकात्मक मान्यता प्रदान करने को भी चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह और अन्य की ओर से पेश हुए अधिवक्ता बरुन सिन्हा ने कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री द्वारा 'चादर' चढ़ाने की प्रथा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में शुरू की गई थी और यह तब से बिना किसी कानूनी या संवैधानिक आधार के जारी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सिन्हा से कहा, ह्यह्यचूंकि यह मामला तर्कसंगत नहीं है, इसलिए न्यायालय इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा।ह्ल्ह सिन्हा ने कहा कि निचली अदालत में इस दावे पर एक दीवानी मुकदमा लंबित है कि दरगाह का निर्माण शिव मंदिर के खंडहरों पर किया गया था।

1670 करोड़ की लागत से सागर द्वीप में बनेगा पुल

एजेंसी। कोलकाता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सागर द्वीप के लिए 1670 करोड़ की लागत वाले पुल की नींव रखी। इस दौरान भाजपा ने सीएम ममता पर जमकर हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती है, वह केवल झूठ फैलाने में विश्वास रखती है। सीएम ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी अपने वैध मतदाता होने का प्रमाण देने के लिए कतारों में खड़ा होने के लिए मजबूर किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह राज्य में एसआईआर के दौरान अपनाए गए श्अमानवीयश तरीके के खिलाफ अदालत का रुख करेंगी। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं, परेशानियों और प्रशासन की मनमानी के कारण कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्होंने कहा, एसआईआर के कारण लोगों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार और इतनी मौतों के खिलाफ हम कल अदालत जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी और एक आम नागरिक के तौर पर इस अमानवीय प्रक्रिया के खिलाफ गुहार लगाऊंगी। मैं खुद एक प्रशिक्षित वकील भी हूं।

शीतलहर और पेड़ पौधों के कारण बिजली आपूर्ति बाधित, विभाग भी परेशान

केटी न्यूज/केसठ

इन दिनों क्षेत्र में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ रहा है। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मार्गों के किनारे तथा बैंकों के आसपास वन विभाग द्वारा लगाए गए बांस, बबूल सहित अन्य पेड़-पौधे अब काफी घने और लंबे हो चुके हैं। इन्हीं रास्तों से होकर बिजली विभाग के 33 हजार, 11 हजार तथा 440 वोल्ट के विद्युत तार गुजरते हैं।कोहरे और तेज ठंड के कारण पेड़ों की डालियां बार बार बिजली के तारों से टकरा रही हैं, जिससे फॉल्ट की समस्या उत्पन्न हो रही है। परिणामस्वरूप क्षेत्र में बार बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। बिजली गुल रहने से जहां घरेलू उपभोक्ता परेशान हैं, वहीं किसान भी सिंचाई कार्य को लेकर भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। रात के समय बिजली कट जाने से अंधेरा छा जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, खाना पकाने सहित दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर क्षेत्र के अत्रि मुनि पांडेय, कमलेश पांडेय, माझिल शर्मा, मुन्ना पांडेय, संतोष आर्य, नरेंद्र पांडेय सहित अन्य लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से नियमित और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

इस संबंध में बिजली विभाग केसठ के कनीय अभियंता अवनीश कुमार ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से अत्यधिक कुहासा पड़ने के कारण पेड़ों की डालियां तारों से टकरा रही हैं, जिससे फॉल्ट की समस्या बढ़ गई है। समस्या के समाधान के लिए विभाग के मानव बल दिन-रात कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पेड़ों की डालियों की कटाई-छंटाई वन विभाग की अनुमति से ही संभव है। यदि वन विभाग की सहमति मिलती है तो तारों से टकरा रही डालियों की छंटाई कर बिजली फॉल्ट की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, विभागीय तालमेल से प्रशासन को और प्रभावी बनाने पर जोर

केटी न्यूज/बक्सर

जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करते हुए जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना रहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक विभागों के बीच समन्वय नहीं होगा, तब तक योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच सकेगा।

किसान पंजीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक में किसान पंजीकरण (फार्मर रजिस्ट्री) को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व, कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल एक विभाग का नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है।

सभी अंचलाधिकारियों को 6 से 9 जनवरी तक कैंप मोड में विशेष अभियान चलाकर अधिकतम किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया, ताकि पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

राजस्व विभाग एवं भूमि बैंक निर्माण पर विशेष फोकस

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान भूमि बैंक निर्माण को उच्च प्राथमिकता का कार्य बताते हुए जिलाधिकारी ने 15 जनवरी तक अंचल एवं अनुमंडल स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।

अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने सभी सरकारी भूमि की स्पष्ट, अद्यतन और समन्वित रिपोर्टिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित आंकड़ों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता स्वीकार्य नहीं होगी।

दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को भूमि बैंक निर्माण की दैनिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया, जबकि उप समाहर्ता भूमि सुधार को सभी अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कैंप मोड में कार्य कराने को कहा गया।

अंचलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर बल

जिलाधिकारी ने सभी अंचलों को आपसी प्रतिस्पर्धा और तालमेल के माध्यम से अपनी रैंकिंग सुधारने का निर्देश दिया। लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकतर परिवादों का समाधान प्रखंड स्तर पर ही किया जाए, ताकि आम नागरिकों को जिला मुख्यालय का अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े।

प्रशासनिक अनुश्रवण और कार्ययोजना

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को अपनी-अपनी मासिक कार्ययोजना तैयार कर संबंधित अनुमंडल के माध्यम से समन्वित रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों और प्रशाखाओं का निरीक्षण कर लंबित फाइलों की समेकित रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा गया।

शिक्षा विभाग की प्रगति

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी विद्यालयों में शौचालयों की कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों से समन्वय कर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में यह जानकारी दी गई कि ई-शिक्षा कोष में बक्सर जिला राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर है। साथ ही सभी विद्यालयों में नियमित रूप से अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

जनहित में समन्वित और समयबद्ध कार्य का आह्वान

बैठक के अंत में जिलाधिकारी साहिला ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों का क्रियान्वयन आपसी समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का असली उद्देश्य कागजी प्रगति नहीं, बल्कि आम जनता तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा।

डुमरांव एसडीपीओ कार्यालय में डीआईजी की सख्त दस्तक, लंबित कांडों पर अफसरों को साफ चेतावनी

- पुराने मामलों के त्वरित निष्पादन का अल्टीमेटम, लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत

केटी न्यूज/डुमरांव

डुमरांव अनुमंडल पुलिस कार्यालय में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब डीआईजी सत्य प्रकाश औचक निरीक्षण पर पहुंचे। यह निरीक्षण लंबित कांडों को लेकर पुलिस की कार्यशैली की कड़ी परीक्षा साबित हुआ। डीआईजी ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया कि अब फाइलों में दबे मामलों और सुस्त अनुसंधान के लिए कोई जगह नहीं है। निरीक्षण की शुरूआत डीआईजी ने कार्यालय में संधारित रजिस्टरों और अभिलेखों से की। एक-एक कर उन्होंने लंबित कांडों की स्थिति, अनुसंधान की प्रगति और निष्पादन की रफ्तार की समीक्षा की। कई मामलों में देरी को लेकर उन्होंने असंतोष जाहिर किया और संबंधित अधिकारियों से सीधे जवाब तलब किया। डीआईजी ने निर्देश दिया कि वर्षों से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और पुलिस पर जनता का भरोसा बना रहे। डीआईजी सत्य प्रकाश ने दो टूक कहा कि अनुसंधान में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुसंधानकताओं को चेताया कि साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और विधिसम्मत कार्रवाई में कोताही सामने आई तो जिम्मेदारी तय होगी। विशेष रूप से गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी शुभम आर्य ने जिले की कानून-व्यवस्था, हालिया घटनाओं और अपराध नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित गश्त, जनता दरबार और जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इस पर डीआईजी ने निर्देश दिया कि इन पहलों का असर जमीन पर दिखना चाहिए। डीआईजी ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनीं और उनके समाधान का भरोसा दिलाया, लेकिन साथ ही अनुशासन और जवाबदेही पर कोई समझौता न करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्ध कार्रवाई ही पुलिस की असली पहचान है। निरीक्षण के अंत में डीआईजी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मियों की सराहना की, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में लंबित कांडों की प्रगति पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

वीर कुंवर सिंह सेतु पर एंडेवर से पकड़ी गई करीब 500 लीटर विदेशी शराब, चालक फरार

केटी न्यूज/बक्सर

बक्सर में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने वाले तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा को जोड़ने वाले वीर कुंवर सिंह सेतु पर रविवार देर रात हुई इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि तस्कर अब लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर शराब की बड़ी खेप बिहार में खपाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल के निर्देश पर उत्पाद इंस्पेक्टर प्रीति कुमारी के नेतृत्व में सेतु पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में रविवार रात करीब एक बजे उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही एक फोर्ड एंडेवर जिसका रजिस्टेज्शन नंबर यूपी 16 एआर 5386 को चेक पोस्ट के पास रोका गया। शुरूआती तौर पर गाड़ी सामान्य लग रही थी, लेकिन तलाशी के दौरान जो सामने आया उसने जांच टीम को भी चौंका दिया। कार के भीतर अलग-अलग नामी ब्रांड की कुल 56 पेटी विदेशी शराब और एक पेटी बीयर बरामद की गई। जब्त शराब

की कुल मात्रा 499.92 लीटर आंकी गई है, जो इसे जिले की हालिया सबसे बड़ी बरामदगी में शामिल करती है। बताया जा रहा है कि शराब को बेहद शातिर तरीके से कार में छिपाया गया था ताकि शक न हो सके। जैसे ही चालक को यह आभास हुआ कि जांच सख्त हो रही है, उसने मौके की अफरातफरी का फायदा उठाया। पीछे खड़ी गाड़ियों की आड़ लेकर वह अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गया। हालांकि, वाहन का नंबर मिलने के बाद उत्पाद विभाग ने तत्परता दिखाते हुए कार मालिक की पहचान कर ली है और उसके खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल ने बताया कि शराब तस्करों के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विभाग की सतर्कता के कारण उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि सीमा क्षेत्रों पर निगरानी और सख्त करने की जरूरत क्यों न हो, ताकि शराब तस्करी की कमर पूरी तरह तोड़ी जा सके।

एक नजर

प्रखंड मुख्यालय में शोक सभा, कर्मठ कर्मी मुनेश्वर प्रसाद को दी गई श्रद्धांजलि

राजपुर। प्रखंड मुख्यालय परिसर में जिला मुख्यालय में कार्यरत कर्मी मुनेश्वर प्रसाद के आकस्मिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई। इस अवसर पर बीडीओ सिद्धार्थ कुमार की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड एवं अंचल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा को संबोधित करते हुए बीडीओ सिद्धार्थ कुमार ने कहा कि मुनेश्वर प्रसाद एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और जिम्मेदार कर्मी थे। वे पिछले कई वर्षों से प्रशासनिक कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहे थे और निर्वाचन कार्य सहित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दायित्वों के निर्वहन में उनकी भूमिका सराहनीय रही। वे हर कार्य को समयबद्ध और गंभीरता से पूरा करने के लिए जाने जाते थे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलती थी। बीडीओ ने कहा कि मुनेश्वर प्रसाद का सरल स्वभाव और सहयोगी भावना उन्हें सभी के बीच प्रिय बनाती थी। सहकर्मियों के साथ उनका व्यवहार सौहार्दपूर्ण था और वे सदैव टीम भावना के साथ कार्य करते थे। उनका अचानक निधन प्रशासनिक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। शोक सभा के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर बीपीआरओ अभिषेक पाठक, शिव शंकर प्रसाद, राजेश कुमार, बबीता कुमारी, योगिता सिंह, समहुता मुखिया प्रतिनिधि फैज उर्फ राहुल सहित प्रखंड एवं अंचल के सभी कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

बसपा बक्सर में फैसलों की राजनीति, संगठन में बढ़ी दरार, सामूहिक 40 ने किया पद व पार्टी को बाय- बाय

बक्सर। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की बक्सर जिला इकाई में संगठनात्मक फैसलों को लेकर उठे विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है। हाल के दिनों में पार्टी द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारी और सदर विधानसभा प्रत्याशी समेत तीन नेताओं के निष्कासन के बाद संगठन के भीतर असंतोष और तेज हो गया, जिसका परिणाम अब सामूहिक इस्तीफे के रूप में सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, पार्टी नेतृत्व द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को कई कार्यकताओं ने असंतुलित और एकतरफा फैसला बताया है। उनका कहना है कि जिन नेताओं को निष्कासित किया गया, वे लंबे समय से पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय थे और बिना व्यापक चर्चा के लिया गया यह कदम संगठन को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाला साबित हुआ। इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों और कार्यकताओं का मानना है कि निष्कासन की कार्रवाई ने पार्टी में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। इससे कार्यकताओं के बीच यह संदेश गया कि संगठन में निष्ठा और मेहनत से ज्यादा महत्व व्यक्तिगत समीकरणों को दिया जा रहा है। इसी वजह से कई जिम्मेदार पदाधिकारियों ने पार्टी से दूरी बनाने का निर्णय लिया। उनका आरोप है कि शीर्ष नेतृत्व के निदेशों की अनदेखी करते हुए बिहार में संगठन को कमजोर करने वाले निर्णय लिए गए, जिससे बसपा की राजनीतिक जमीन खिसकती चली गई। लगातार उपेक्षा, संवादहीनता और सम्मान के अभाव ने असंतोष को और गहरा किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पहले निष्कासन और अब सामूहिक इस्तीफों की कड़ी ने बक्सर में बसपा संगठन की अंदरूनी चुनौतियों को उजागर कर दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी नेतृत्व इस संकट से उबरने के लिए क्या रणनीति अपनाता है, क्योंकि यह घटनाक्रम जिले की राजनीति को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

नये साल में चला तबादला एक्सप्रेस, बक्सर के पांच थानाध्यक्ष समेत सात पदाधिकारी बदले, एसपी के अनुशंसा पर डीआईजी ने किया

- औद्योगिक, अनुसूचित जाति/जनजाति, धनसोई, नावानगर व कृष्णाब्रह्म थानों को मिले नये थानाध्यक्ष

केटी न्यूज/बक्सर

नये साल में पुलिस महकमा ने तबादला एक्सप्रेस चलाया है। बक्सर एसपी शुभम आर्य के अनुशंसा पर सोमवार को शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश ने जिले के पांच थानाध्यक्षों को बदल, उनके जगह पुलिस केन्द्र में तैनात पांच पदाधिकारियों को कमान सौंपी है।

डीआईजी द्वारा जारी सूची के अनुसार बक्सर औद्योगिक थाने के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष संजय कुमार-2 को औद्योगिक थाने से हटा पुलिस केन्द्र भेजा गया है, जबकि उनकी जगह पुलिस केन्द्र से पुलिस निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह को औद्योगिक थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं, ब्रह्मपुर थाने में तैनात राहुल कुमार को अनुसूचित जाति/जनजाति थाना का थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि यहां के थानाध्यक्ष रहे मनीष कुमार शर्मा को पुलिस केन्द्र भेजा गया है। इसके अलावे रवि कुमार को कृष्णाब्रह्म थाने की कमान सौंपी गई है, जबकि कृष्णाब्रह्म के निवर्तमान थानाध्यक्ष संदीप कुमार राम को पुलिस केन्द्र भेजा गया, धनसोई थानाध्यक्ष रितेश कुमार दूबे की जगह विकास कुमार-1 को तथा नगर थाने में तैनात प्रफुल्ल कुमार को नावानगर थाने का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, नावानगर के निवर्तमान थानाध्यक्ष कुसुम कुमार केशरी भी फिलहाल पुलिस केन्द्र बक्सर में अपनी सेवाएं देंगे।

वहीं, डुमरांव के सर्किल इंस्पेक्टर श्रीनाथ कुमार के जगह अरविंद कुमार को डुमरांव का नया सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है, जबकि पुलिस केन्द्र में तैनात संतोष कुमार को एएलटीएफ/एएनटीएफ का प्रभारी बनाया गया है।

डीआईजी ने सभी नये पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर अपने नये कार्यस्थल पर योगदान करने का निर्देश दिया है। नये साल में पुलिस महकमे में हुए इस फेरबदल को विधि-व्यवस्था दुरूस्त करने के रूप में देखा जा रहा है।

एसपी के जनता दरबार में उठा नया भोजपुर पैक्स बैंक के गबन का मुद्दा, सामूहिक एफआईआर के दिए आदेश

ए एसपी साहेब... हमारा बेटी के बियाह करेके बा, पैक्स के बैंक वाला हमार जमा पईसा नईखे देत

- पैक्स द्वारा संचालित बैंक पर 1.8 करोड़ का लगा गबन का आरोप
- फरियाद लेकर 20 से अधिक लोग पहुंचे, पिड़ा सुन दंग रह गए एसपी
- महिला का आवेदन की एंट्री नहीं करने पर एसपी ने जमादार को सस्पेंड करने का सुनाया फरमान

केटी न्यूज/डुमरांव

नया भोजपुर थाने में सोमवार को एसपी शुभम आर्य ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जहां पंचायत प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकताओं ने सामूहिक समस्याओं के प्रति पुलिस कप्तान का ध्यान आकृष्ट कराया, वहीं आम लोगों ने व्यक्तिगत समस्याओं को भी एसपी के समक्ष रखा। एसपी ने कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया, जबकि कुछ मामलों में संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर लोगों को न्याय दिलाने व उक्त कार्रवाई से उन्हें अवगत कराने का निर्देश दिया। जबकि कई मामलों में एसपी ने संबंधित विभाग से समन्वय बना सामूहिक मुद्दों के समाधान का आश्वासन लोगों को दिया। इस दौरान कुल पांच सामजिक मुद्दे समेत दो दर्जन से अधिक मामले आए। एसपी के इस जनता दरबार में सबसे अधिक नया भोजपुर पैक्स द्वारा जमा वृद्धि योजना के तहत संचालित बैंक के गबन का मामला उठा। एसपी के जनता दरबार में नया भोजपुर पैक्स द्वारा जमा वृद्धि योजना के तहत संचालित किए गए बैंक के गबन का मुद्दा छाया रहा। करीब दर्जन भर से अधिक शिकायतकर्ताओं ने एसपी को बताया कि पैक्स बैंक द्वारा दो करोड़ से अधिक रूपए का गबन किया गया है, जो गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा था। ग्रामीणों ने बताया कि जो सामाजिक या आर्थिक रूप से मजबूत थे उनका पैसा पैक्स ने लौटा दिया, जबकि संचालक व उसके लोगों ने गरीबों को लंबे समय तक झांसे में रखा तथा अधिकांश लोगों का पासबुक भी अपने पास जब्त कर लिया। वहीं, अब पैसा मांगने पर डांटकर भगाया जा रहा है।

हुजूर फरवरी में शादी है, अभी तक नहीं मिला जमा पैसा

इस दौरान सुनीता कुमारी ने एसपी को बताया कि हुजूर फरवरी में मेरे घर लड़की की शादी है, पैक्स में मेरे घरवालों ने 86 हजार रूपए जमा कराए है, लेकिन अब वह पैसा नहीं मिल रहा है। पैक्स बैंक में भी ताला लटका हुआ है। सुनीता का कहना था कि पैसे के अभाव में शादी टूटने की नौबत आ गई है। अभी तक उस निमित कुछ तैयारी भी हमलोग नहीं कर पा रहे है, जबकि स्थानीय पुलिस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। बता दें कि पूर्व में यह विवाद थाना पहुंचा था, जहां थाना द्वारा समझौता कराते हुए पैक्स संचालक को कुछ समय निर्धारित कर लोगों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन संचालक द्वारा अबतक अधिकांश लोगों का पैसा नहीं लौटाया गया है। कुछ ऐसा ही आरोप नया भोजपुर के राजेश कुमार, असगर कुरैशी, रिंकू कुरैशी, गुड़िया खातून, शमशाद, गोरख प्रसाद, हस्साम खां, हरेराम यादव समेत कई अन्य लोगों व महिलाओं ने पैक्स बैंक द्वारा अबतक पैसा नहीं लौटाने की शिकायत की।

एसपी बोले... सामूहिक आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर करें कार्रवाई

लोगों की इस समस्या को सुन एसपी काफी सख्त हो गए। उन्होंने इसे गंभीर अपराध माना तथा नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार को लोगों से सामूहिक आवेदन लेकर एफआईआर दर्ज कर संचालक तथा संबंधित अन्य दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि हर हाल में लोगों का जमा पैसा वापस होना चाहिए।

बोले लोग वर्षों से नहीं हुआ है पैक्स बैंक का ऑडिट

इस दौरान नया भोजपुर के ग्रामीणों ने कहा कि पैक्स द्वारा संचालित इस बैंक में बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए है, जबकि विभाग द्वारा वर्षों से इसका आडिट नहीं किया गया है। लोगों ने इस पैक्स तथा इसके द्वारा संचालित बैंक का आडिट कराने की मांग किया और कहा कि यदि गहराई से जांच की जाएगी तो गबन की राशि बढ़ सकती है।

आवेदन एंट्री नहीं करने पर नपे नया भोजपुर थाने के जमादार

एसपी के जनता दरबार में बभनौल अड्डा से पहुंची शबनम खातून के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने नया भोजपुरे थाने में पद स्थापित जमादार अमृत लाल को सस्पेंड करने का फरमान सुनाया। दरअसल शबनम रविवार की शाम भी थाने पर आई थी तथा एक आवेदन भी ओडी में मौजूद जमादार अमृत लाल को दी थी, लेकिन उन्होंने महिला के आवेदन की एंट्री तक नहीं की थी। एसपी ने इसे लापरवाही माना तथा तत्काल प्रभाव से जमादार को सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया। वहीं, जनता दरबार में शबनम ने एसपी को आवेदन दे बताया कि उसके पति ट्रक ड्राइवर है तथा नया भोजपुर निवासी महताब खां का ट्रक चलाते थे। वे दो साल तक उनका ट्रक चलाए, इस दौरान महताब ने उन्हें एक साल की मजदूरी ही दी है, अभी भी उसके पास मेरे पति का 80 हजार रूपए बकाया है, जिसे देने में वह आनाकानी कर रहा है। एसपी ने नया भोजपुर थानाध्यक्ष को इस मामले में आरोपित को बुला पूछताछ करने तथा बकाया पैसा दिलवाने का निर्देश दिया।

माता-पिता की हो चुकी है मृत्यु चाचा घर पर कर लिए है कब्जा

एसपी के जनता दरबार में कई ऐसे मामले भी सामने आए, जिसे सुन लोग द्रवित हो उठे। इसी कड़ी में नया भोजपुर निवासी शिवानी कुमारी ने एसपी को आवेदन दे बताई कि उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। एक छोटा भाई है, जिसकी परवरिश की जिम्मेवारी भी अब मेरे जिम्मे ही है। शिवानी ने एसपी को बताया कि उसके चाचा रमेश पैतृक घर पर कब्जा जमा लिए है। गांव के बुद्धिजीवियों व पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पंचायती में जो फैसला सुनाया गया था, चाचा उसे भी नहीं मान रहे है। एसपी ने नया भोजपुर थानाध्यक्ष को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उक्त लड़की को जरूर न्याय मिले, ऐसा प्रयास करना है।

जमीन विवाद के मामले रहे नगण्य

एसपी के जनता दरबार में जमीन विवाद संबंधित मात्र एक मामला ही आया। सिमरी की पार्वती देवी ने एसपी के जनता दरबार में जमीन विवाद का मुद्दा उठाया, इस दौरान एसपी ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया। हालांकि, डुमरांव थाने में आयोजित जनता दरबार की अपेक्षा यहां जमीन विवाद संबंधित मामले देखने को नहीं मिले। जनता दरबार के दौरान एसपी के साथ डुमरांव एसडीपीओ पोलस्त कुमार, पुलिस निरीक्षक श्रीनाथ कुमार, नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार, अपर थानाध्यक्ष सुमन कुमार, वार्ड पार्षद प्रदीप वर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल यादव, विजय राम समेत बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद थे।

एसपी के जनता दरबार में नया भोजपुर में शराब बिक्री से लेकर फोरलेन पर कट बनवाने तक की लगी गुहार

- वार्ड पार्षदों व सामाजिक कार्यकर्ताओं उठाए कई मुद्दे, एसपी ने दिया सकारात्मक जबाव

केटी न्यूज/डुमरांव

नया भोजपुर थाने में आयोजित एसपी के जनता दरबार में जहां आम लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी, वहीं वार्ड सदस्यों व सामाजिक-राजनैतिक कार्यकताओं ने सामाजिक मुद्दों को जनता दरबार में उठाया, जिस पर एसपी ने सकारात्मक आश्वासन दिया।

सामाजिक मुद्दों की शुरूआत नया भोजपुर निवासी व डुमरांव नगर परिषद के वार्ड सात के पार्षद प्रतिनिधि प्रदीप कुमार वर्मा ने की। उन्होंने एसपी के समक्ष मुद्दा उठाया कि नया भोजपुर लोहारटोली चौके के पास स्थित हिन्दी प्लस टू उच्च विद्यालय में बड़ी संख्या में लड़किया भी पढ़ती है। स्कूल लगने तथा छुट्टी के समय मनचले छात्राओं पर खुलेआम फब्तियां कसते है तथा छेड़खानी भी करते है। उन्होंने कहा कि मनचलों की करतूत से उक्त विद्यालय के शिक्षक भी आहत रहते है, जबकि छात्राएं शर्मसार होती है। एसपी ने थानाध्यक्ष को स्कूल लगने व छुट्टी के समय पुलिस गश्त कराने तथा मनचलों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।

वहीं, एक अन्य वार्ड पार्षद विजय राम ने नया भोजपुर थाने के सामने फोरलेन पर कट बनवाने की मांग की और कहा कि कट के अभाव में सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए बड़का ढकाईच तक जाना पड़ रहा है। इस पर एसपी ने कहा कि वे खुद इस पथ का मुआयना करेंगे तथा एनएचएआई के अधिकारियों से बात कर इस जगह कट बनवाने को कहेंगे।

राजद नेता अनिल कुमार यादव ने नया भोजपुर थाने का भवन शीघ्र बनवाने की मांग की। एसपी ने कहा कि इस दिशा में विभागीय प्रयास चल रहा है, जल्दी ही नया भोजपुर थाने को अपना भवन नसीब होगा।

इसके अलावे उत्पल यादव ने नया भोजपुर सब्जी मंडी के पास फोरलेन पर लगने वाले अवैध पार्किंग हटवाने, वहां सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की तथा कहा कि नया भोजपुर में शराब की बिक्री हो रही है। उत्पल ने कहा कि इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी इस गांव में शराब की बिक्री हो रही है। एसपी ने थानाध्यक्ष को शराब तस्करी पर लगाम लगाने तथा रिकवरी बढ़ाने का निर्देश दिया।

पत्नी दो बच्चों को छोड़ हो गई है फरार, पुलिस नहीं कर रही बरामद

वहीं, नया भोजपुर निवासी राजकुमार बिंद ने एसपी को आवेदन दे बताया कि उनकी पत्नी दो बच्चों को छोड़ 19 दिसंबर को ही गांव के ही कृष्णा चौधरी के साथ फरार हो गई है। राजकुमार का कहना था कि उसने इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे बरामद नहीं कर सकी है। एसपी ने इस मामले में तेजी लाने तथा आरोपित व उसकी पत्नी को बरामद करने का निर्देश दिया।

सिमरी थाने के पुलिस पदाधिकारी पर गाड़ी छोड़ने के लिए पैसा मांगने का लगा आरोप

एसपी के जनता दरबार में सिमरी से आई देवान्ति देवी ने बताया कि उसके पुत्र छोटेलाल को पुलिस ने काजीपुर से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने उसकी बाइक भी जब्त कर ली थी। देवान्ति ने बताया कि अब पुलिस वाहन को छोड़ने के लिए 50 हजार रूपए की मांग कर रही है। उन्होंने सिमरी थाने में पद स्थापित एक दारोगा का नाम का जिक्र भी अपने आवेदन में किया है। एसपी ने इसकी जांच कर दोष साबित होने पर कार्रवाई का भरोसा दिया।

सनातन आस्था का महासंगम, मोतिहारी में स्थापित होगा विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग

एजेंसी। पटना

मोतिहारी में आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग अब तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 45 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर जल्द ही मोतिहारी पहुंचने वाला है। इस विशाल शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी को कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया गांव में बन रहे विराट रामायण मंदिर में की जाएगी। इसे लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह और श्रद्धा का माहौल है।यह पूरी घटना मोतिहारी जिले के कल्याणपुर प्रखंड स्थित कैथवलिया गांव से जुड़ी है, जहां विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी मंदिर में स्थापित किए जाने वाला यह ऐतिहासिक शिवलिंग 21 नवंबर को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से रवाना हुआ था, जो अब कुछ ही दिनों में मोतिहारी पहुंचने वाला है।मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि विराट रामायण मंदिर आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस मंदिर का निर्माण महावीर मंदिर न्यास समिति द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर के प्रवेश द्वार, गणेश स्थल, सिंह द्वार, नंदी स्थल, शिवलिंग स्थल और गर्भगृह की पाइलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। यह विराट मंदिर आकार में करीब 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। मंदिर परिसर में कुल 18 शिखर और 22 छोटे-बड़े मंदिर बनाए जाएंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। इस भव्य मंदिर का शिलान्यास 20 जून 2023 को किया गया था, जिसके बाद से निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। बताया गया है कि फिलहाल शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, जबकि इसकी प्राण-प्रतिष्ठा बाद में विधि-विधान से की जाएगी। यह शिवलिंग 33 फीट लंबा और करीब 210 मीट्रिक टन वजनी है। इसे एक ही ब्लैक ग्रेनाइट मोनोलिथ पत्थर से तैयार किया गया है।

तमिलनाडु के पट्टीकाडु गांव में इस शिवलिंग को तैयार करने में कारीगरों को पूरे 10 साल लगे। खास बात यह है कि इस विशाल शिवलिंग पर 1008 सहस्त्रलिंगम भी उकेरे गए हैं। इस भारी-भरकम शिवलिंग को 96 चक्का वाले विशेष ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से लाया जा रहा है, जो रास्ते भर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल यह शिवलिंग बिहार के गोपालगंज तक पहुंच चुका है, जहां जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजा-पाठ किया जा रहा है और भव्य स्वागत किया जा रहा है।

24 जनवरी को कपूर्री ठाकुर जयंती पर समस्तीपुर आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तैयारियां जोरों पर

एजेंसी। पटना

भारत रत्न जननायक कपूर्री ठाकुर की जयंती के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 जनवरी को समस्तीपुर पहुंचेंगे। वे जननायक कपूर्री ठाकुर के पैतृक गांव कपूर्रीग्राम आने वाले हैं, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिलाधिकारी के नेतृत्व में समाहरणालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कपूर्रीग्राम पहुंचकर जननायक कपूर्री ठाकुर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे और सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री गोकुल फुलेश्वरी महाविद्यालय में स्थापित कपूर्री ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत पंचायत आने की भी संभावना जताई जा रही है, जहां वे बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं।सूत्रों के अनुसार, केवस निजामत पंचायत क्षेत्र में कई तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री इन स्टॉलों का जायजा लेंगे और सरकारी योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है।

लगातार निरीक्षण और विकास कार्य

मुख्यमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी पिछले छह दिनों से लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। शिवगंगा तालाब के मेंटेनेंस का कार्य शुरू कर दिया गया है। पीएचईडी विभाग द्वारा समरसेबल की गई है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पुस्तकालयों में डब्लू पीए के तहत रंग-रोगन का काम भी तेजी से चल रहा है।

सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान

क्षेत्र में साफ-सफाई के कार्यों में भी काफी तेजी आई है। विभिन्न विभागों के अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे में किसी तरह की कमी न रह जाए। स्थानीय मुखिया राजीव कुमार राय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की संभावना को देखते हुए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सफाई का कार्य लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी काफी तैयारियां की गई थीं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ सके थे। इस बार पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री समस्तीपुर आएंगे।

भू-अर्जन मुआवजा को लेकर रैयतों और प्रशासन के बीच बनी असहमति

केटी न्यूज/केसठ

प्रखंड क्षेत्र में अंचल निर्माण एवं विकास कार्य के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के मुआवजा भुगतान को लेकर रैयतों और प्रशासन के बीच असहमति बनी हुई है। प्रभावित भू-स्वामियों ने भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार तय करने की मांग करते हुए अंचल पदाधिकारी केसठ को आवेदन सौंपा है। रैयतों का कहना है कि अधिग्रहण के समय उन्हें यह बताया गया था कि भूमि का भुगतान वर्तमान सरकारी दर पर डिसमिल के अनुसार किया जाएगा, जिसके आधार पर उन्होंने स्वीकृति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया। रैयतों के अनुसार अधिग्रहित भूमि गांव के बीचों-बीच स्थित है तथा अंचल मुख्यालय से सटी होने के कारण इसकी प्रकृति आवासीय है। रैयतों ने आरोप लगाया कि अब उन्हें वर्ष 2013-14 के सरकारी एलआर रेट के आधार पर कृषि भूमि मानते हुए चार गुना मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जो वर्तमान दर की तुलना में काफी कम है। इतना कम भुगतान

मिलने पर वे वैकल्पिक भूमि खरीदकर आवास निर्माण करने में असमर्थ होंगे। मामले को लेकर सोमवार को मनरेगा भवन के सभागार में बीडीओ विजय कुमार सौरभ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें केसठ पंचायत के मुखिया अरविंद कुमार यादव उर्फ गामा पहलवान तथा प्रभावित रैयत शामिल हुए। बैठक के दौरान बीडीओ ने स्पष्ट किया कि जिस दर पर भूमि का भुगतान स्वीकृत किया गया है, उसी दर से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राशि का आवंटन हो चुका है, ऐसे में अब मुआवजा दर में बदलाव संभव नहीं है। इस पर रैयतों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उस समय और वर्तमान में काफी अंतर आ चुका है। उन्होंने मांग की कि मुआवजा राशि शुद्ध और एकमुश्त भुगतान के रूप में दी जाए, न कि किस्तों में। बीडीओ ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जिला के वरीय पदाधिकारियों से वार्ता की जाएगी। हालांकि बैठक के बाद भी कुछ रैयतों का विरोध जारी रहा।

सरकारी लाइब्रेरी में चोरी का प्रयास, ताला तोड़ अज्ञात चोर फरार

- सीसीटीवी, बिजली तार चोरी, पुलिस जांच में जुटी सिमरी थाना

केटी न्यूज/सिमरी

सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिहार पंचायत स्थित मध्य विद्यालय बड़का गांव में सरकार द्वारा संचालित लाइब्रेरी में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने देर रात लाइब्रेरी को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। इस संबंध में विद्यालय के शिक्षक कमलेश कुमार यादव द्वारा सिमरी थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना दिनांक 04 जनवरी की रात की बताई जा रही है। अज्ञात चोरों ने लाइब्रेरी के बरामदे में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर चोरी कर लिया। इसके अलावा लैब रूम के दरवाजे पर लगे पर्दे, बिजली के तार को काटकर भी चुरा लिया गया। चोरों ने लैब रूम का ताला तोड़ने का

भी प्रयास किया, लेकिन ताला पूरी तरह नहीं टूट पाया, जिससे वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके और उनके मंसूबे नाकाम हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद विद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया। शिक्षक एवं स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकारी संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में सिमरी थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष अर्जुन कुमार सिंह ने बताया कि घटना को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है तथा आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही अज्ञात चोरों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पटना से हर जिले के लिए सरकारी बस, बिहार से दिल्ली समेत 6 राज्यों को सीधे जोड़ने की तैयारी

एजेंसी। पटना

बिहार की राजनीति में अब कनेक्टिविटी नया चुनावी नारा बनती दिख रही है। वर्षों से ट्रेन की भीड़, टिकट न मिलने की परेशानी और लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रहे बिहारवासियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सड़क परिवहन के मोर्चे पर बड़ा दांव चला है। सरकार का फोकस साफ है—अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए लोगों को सिर्फ रेलवे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि बस सेवा के जरिए बिहार को देश के कोने-कोने से जोड़ा जाएगा। परिवहन विभाग ने 6 राज्यों और 60 से अधिक शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह फैसला न केवल यात्रियों की सुविधा से जुड़ा है, बल्कि आने वाले चुनावी माहौल में इसे विकास और जनहित की

राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से न सिर्फ आम लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि बिहार की छवि भी एक कनेक्टेड स्टेटके रूप में मजबूत होगी। इस पूरे फैसले के केंद्र में हैं राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार के उन सभी प्रखंडों को, जहां आबादी 50 हजार से ज्यादा है, हर हाल में बस सुविधा से जोड़ा जाएगा। उनका दावा है कि अब बिहार के अलग-अलग जिलों से सीधे दूसरे राज्यों और बड़े शहरों के लिए बसें चलेंगी, जिससे यात्रियों को बार-बार पटना या बड़े जंक्शन पर आने की मजबूरी नहीं रहेगी। इससे समय, पैसा और मेहनत—तीनों की बचत होगी। सरकार की योजना के मुताबिक, अगले दो महीनों के भीतर करीब 150 नई बसें सड़कों पर उतरेंगी। यह शुरूआत मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में बसों की संख्या और रूट दोनों बढ़ाए जाएंगे। खास बात यह है कि इस पूरी योजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है। परिवहन विभाग ने लगभग 650 बसों को पीपीपी मोड में चलाने के लिए निजी बस मालिकों से आवेदन मांगे हैं। फिलहाल भी बिहार में करीब 1200 बसें इसी पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को पहले से ही फायदा मिल रहा है। सरकार का मानना है कि निजी भागीदारी से न सिर्फ बसों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। समय पर बसें, बेहतर मेंटेनेंस और अलग-अलग कैटेगरी की सुविधाएं यात्रियों को आकर्षित करेंगी। राज्यवार बात करें तो सबसे ज्यादा बसें झारखंड के लिए प्रस्तावित हैं—करीब 90 बसें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए 34, पश्चिम बंगाल के लिए 45, ओडिशा के लिए 16, छत्तीसगढ़ के लिए 28 और दिल्ली के लिए 10 बसें चलाई जाएंगी। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर रूट तय किए हैं। बसों की कैटेगरी भी यात्रियों की जेब और सुविधा के हिसाब से रखी गई है। प्रस्ताव के मुताबिक, 400 नॉन-एसी बसें, 200 एसी बसें और 50 लग्जरी बसें सड़कों पर उतरेंगी।

क्रिकेट मैच देखकर लौटते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा, दो युवकों की गई जान

एजेंसी। पटना

मुजफ्फरपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक क्रिकेट मैच देखकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हुए हादसे का शिकार हो गए। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में चीख-पुकार मच गई। हादसा साहेबगंज थाना क्षेत्र में हुआ, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।जानकारी के अनुसार, यह भीषण सड़क दुर्घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र के साहेबगंजझफुलवरिया रोड के पास हुई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों की पहचान चंद्रिका कुमार साह (28 वर्ष), निवासी राजपुर कुंवर टोला, पिता शंभू साह और दूसरे युवक की पहचान राजू कुमार पटेल, पिता प्रभु राय, निवासी राजेपुर थाना क्षेत्र के रूप में की है।बताया जा रहा है कि दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर साहेबगंज में आयोजित दिवा-रात्रि क्रिकेट मैच देखकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में वे सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही साहेबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बाइक पर सवार दोनों युवक तेज रफ्तार में आ रहे थे। उसी समय एक ट्रक को एक मारुति कार ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान अचानक सामने से एक सरकारी बस आ गई। इससे अफरा-तफरी मच गई और बाइक सवार दोनों युवक जल्दबाजी में निकलने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई।टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ओवरटेक करने के दौरान यह सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।

एक नजर

आवास प्लस जांच में तेजी लाने का बीडीओ का निर्देश

सिमरी। सिमरी प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में इंदिरा आवास सहायकों एवं पंचायत रोजगार सेवकों (पीआरएस) के साथ एक आवश्यक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे, निर्माण कार्यों की प्रगति एवं जिओ टैगिंग की स्थिति की समीक्षा करना था। बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी आवास सहायकों और पीआरएस कर्मियों को आवास प्लस जांच कार्य में तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों को इंदिरा आवास योजना की पहली और दूसरी किस्त प्राप्त हो चुकी है, उनके निर्मित आवासों का अविलंब जिओ टैगिंग सुनिश्चित किया जाए। बीडीओ ने विकास कार्यों में शिथिलता पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिकायत मिलने पर नियमों के अनुरूप कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी कर्मी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर आवास का लाभ मिल सके और सरकारी योजनाओं का उद्देश्य पूर्ण हो। बैठक के दौरान कार्य प्रगति से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मौजूद इंदिरा आवास सहायकों ने विगत सात माह से वेतन का भुगतान नहीं होने की समस्या को उठाया। सहायकों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से शीघ्र वेतन भुगतान कराने की मांग की, जिस पर बीडीओ ने मामले को वरीय पदाधिकारियों के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। बैठक में रंजीत कुमार, भृगुनाथ कुमार, प्रसाद हरे राम, संदीप शर्मा, प्रियंका कुमारी, लेखपाल अंचला कुमारी, सुपरवाइजर राजेश कुमार, राजेश प्रसाद, संदीप सिंह, पीआरएस अल्ताफ आलम सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

ईकेवाईसी और फार्मर आईडी बनाने के लिये पंचायतों में लगेंगे शिविर, तैयारी पूरी

डुमरांव। किसानों को ईकेवाईसी और फार्मर आईडी बनाने के लिये काफी परेशान थे, जिसकी शिकायत डीएम तक पहुंची थी। फिर डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को पंचायतों में शिविर लगाकर बनाने का आदेश दिया है। उसी आदेश के आलोक में मंगलवार से शिविर लगाने का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। डुमरांव प्रखंड के नया भोजपुर, पुराना भोजपुर, चिलहरी, अरियांव, कनझरूआ, सोवां, नंदन और कुशलपुर में शिविर लगाया जाएगा। शिविर लगने की जानकारी जैसे किसानों को मिली काफी खुश हुए।

खाद बिक्रेताओं को उचित दर पर बिक्री करने का एडीएसओ ने दिया निर्देश

डुमरांव। नया भोजपुर के ईफको बाजार का अनुमंडल कृषि पदाधिकारी वेद प्रकाश ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया की बिक्री के लिये रखे यूरिया सहित अन्य खाद का मूल्य टैगिंग नहीं किया गया था। उन्होंने सभी दुकानदारों को अपने सामने मूल्य टैगिंग करवाते हुए कहा कि इसे हर समय लगे रहना चाहिए, जिससे किसानों को उचि मूल्य पर खाद खरीदने में कोई परेशानी नहीं हो। मालूम हो कि दिशा की बैठक में खाद ब्लैक में अधिक रेट पर बिकने की बात उठी थी, जिस पर डीएम ने सभी खाद बिक्रेताओं को उचित रेट पर खाद को बिक्री करने का आदेश दिया था। उसी आदेश के आलोक में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी वेद प्रकाश ने सोमवार को नया भोजपुर स्थित ईफको बाजार नया भोजपुर का निरीक्षण किया। बाजर के जितने सेंटर थे, सभी को मूल्य टैगिंग करने का आदेश दिया। साथ ही सभी से कहा कि सबसे अधिक मांग यूरिया की है, लिहाजा जो निर्धारित मूल्य 266 रूपया पचास पैसा है, उसका चार्ट हमेशा लगा रहना चाहिए। मालूम हो कि जिले का डुमरांव प्रखंड सबसे बड़ा है, इस प्रखंड में कुल सोलह पंचायत पहले हुआ करते थे, लेकिन दो पंचायत भोजपंर कदीम व भोजपुर जदीद डुमरांव नगर परिषद के विस्तारित क्षेत्र में शामिल हो गए, जिससे अब 14 पंचायत ही रह गए हैं। इन चौदह पंचायतों में रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 24 हजार 500 है। पहले यूरिया खाद 3 सौ 50 रूपया पर बिक्री दुकानदारों द्वारा किया जाता था, जिसकी शिकायत डीएम से लेकर अन्य अधिकारियों तक की गई थी। उचित मूल्य पर खाद की बिक्री होने पर किसानों में खुशी है।

प्रखंड मुख्यालय में शोक सभा, कर्मठ कर्मी मुनेश्वर प्रसाद को दी गई श्रद्धांजलि

राजपुर। प्रखंड मुख्यालय परिसर में जिला मुख्यालय में कार्यरत कर्मी मुनेश्वर प्रसाद के आकस्मिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई। इस अवसर पर बीडीओ सिद्धार्थ कुमार की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड एवं अंचल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा को संबोधित करते हुए बीडीओ सिद्धार्थ कुमार ने कहा कि मुनेश्वर प्रसाद एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और जिम्मेदार कर्मी थे। वे पिछले कई वर्षों से प्रशासनिक कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहे थे और निर्वाचन कार्य सहित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दायित्वों के निर्वहन में उनकी भूमिका सराहनीय रही। वे हर कार्य को समयबद्ध और गंभीरता से पूरा करने के लिए जाने जाते थे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलती थी। बीडीओ ने कहा कि मुनेश्वर प्रसाद का सरल स्वभाव और सहयोगी भावना उन्हें सभी के बीच प्रिय बनाती थी। सहकर्मियों के साथ उनका व्यवहार सौहार्दपूर्ण था और वे सदैव टीम भावना के साथ कार्य करते थे। उनका अचानक निधन प्रशासनिक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। शोक सभा के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर बीपीआरओ अभिषेक पाठक, शिव शंकर प्रसाद, राजेश कुमार, बबीता कुमारी, योगिता सिंह, समहुता मुखिया प्रतिनिधि फैज उर्फ राहुल सहित प्रखंड एवं अंचल के सभी कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

राजगीर में शुरू होगा बिहार का पहला वाटर लेजर लाइट एंड साउंड शो

एजेंसी। पटना

बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में पर्यटन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 1 मार्च से राजगीर स्थित पांडू पोखर में राज्य का पहला वाटर लेजर लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों के लिए शुरू होने जा रहा है। पर्यटन विभाग की इस महत्वाकांक्षी पहल के बाद पांडू पोखर न केवल राजगीर, बल्कि पूरे बिहार का एक प्रमुख और आधुनिक पर्यटन आकर्षण बनने की ओर अग्रसर है। पांडू पोखर परिसर को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का कार्य अब अंतिम चरण में है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टीम लगातार स्थल

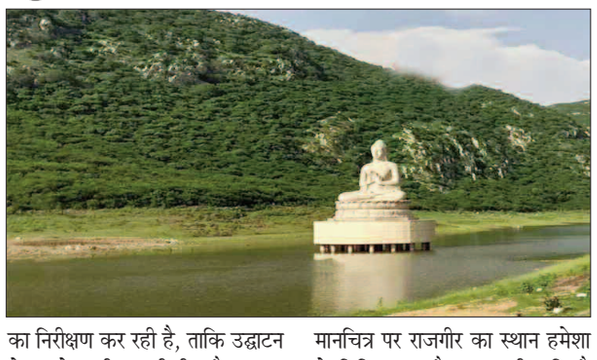

का निरीक्षण कर रही है, ताकि उद्घाटन से पहले सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा किया जा सके। विभाग का लक्ष्य है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान किया जाए। बिहार के पर्यटन मानचित्र पर राजगीर का स्थान हमेशा से विशिष्ट रहा है। यह वही भूमि है जहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने तपस्या और उपदेश दिए। अब आधुनिक तकनीक के सहारे राजगीर के इसी गौरवशाली अतीत को नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी 1 मार्च से शुरू होने वाला वाटर लेजर लाइट एंड साउंड शो न केवल मनोरंजन करेगा, बल्कि दर्शकों को इतिहास से भी जोड़ेगा। शाम के समय पांडू पोखर के शांत जल क्षेत्र में जब लेजर किरणें, रंग-बिरंगी रोशनियां और प्रभावशाली ध्वनि गूंजेंगी, तो पूरा वातावरण जीवंत हो उठेगा। सदियों पुरानी कहानियां पानी की विशाल स्क्रीन पर तैरती हुई दिखाई देंगी, जो दर्शकों को एक अलग ही कालखंड में ले जाएंगी। यह भव्य शो पांडू पोखर के जल क्षेत्र में प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। पानी की धाराओं पर लेजर तकनीक, आधुनिक लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स के जरिए राजगीर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा। दर्शक अपनी सीट पर बैठे-बैठे उस युग की यात्रा करेंगे, जब राजगीर ज्ञान, धर्म और संस्कृति का वैश्विक केंद्र हुआ करता था। शो की सबसे बड़ी खासियत इसकी वाटर स्क्रीन है। इस जल-आधारित स्क्रीन पर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और राजगीर के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी कथाओं को जीवंत रूप में दिखाया जाएगा। पानी पर बनती यह विशाल स्क्रीन दृश्य को और अधिक प्रभावशाली बना देगी। रोशनी, ध्वनि और कथा का यह समन्वय श्रद्धा, रोमांच और इतिहास–तीनों का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। इस वाटर लेजर शो में रेनबो शूटर जेट, हाई जेट, डांसिंग फाउंटेन, डायमंड जेट, वाटर स्क्रीन और सनबर्स्ट जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया गया है, जो संगीत की धुनों पर पानी और रोशनी का अद्भुत प्रदर्शन करेगा। पानी, प्रकाश और संगीत का यह तालमेल पर्यटकों के लिए लंबे समय तक यादगार अनुभव बनेगा। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस शो के शुरू होने से राजगीर में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भूमाफियाओं पर सख्त तेवर : मार्च के बाद सीधे एक्शन, कोई दबाव नहीं चलेगा : विजय सिन्हा

एजेंसी। पटना

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा और मार्च के बाद सीधे कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ह्लमार्च के बाद जो महात्मा लोग बैठे हुए हैं, यानी जो भूमाफिया व्यवस्था के भीतर या बाहर बैठकर जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी कर रहे हैं, उन पर ही हमारी नजर है। मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार भूमि सुधार और राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी फर्जी दस्तावेज, गलत म्यूटेशन, जबरन कब्जा और झूठे मुकदमों के सहारे आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि अब ऐसे

लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ह्लअब सीधे एक्शन का समय है। किसी भी तरह का दबाव, सिफारिश या राजनीतिक संरक्षण अब काम नहीं करेगा, उन्होंने मंच से स्पष्ट संदेश दिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी-अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। कई मामलों में जमीन पर फर्जी दस्तावेज लगाने, गलत तरीके से म्यूटेशन कराने, जमीन मापी में घोटाले और थाना स्तर पर जबरन मुकदमे दर्ज कराने की शिकायतें सामने आईं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि विवाद बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ता है। किसान, छोटे जमीन मालिक और कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें न्याय मिले। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत भूमाफियाओं के साथ पाई गई तो उसके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। ह्लअब फाइल दबाकर बैठने का दौर खत्म हो गया है, मंत्री ने कहा। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने भूमि से जुड़े मामलों के समाधान के लिए कई स्तरों पर सुधारात्मक कदम उठाए हैं। ऑनलाइन म्यूटेशन, डिजिटल रिकॉर्ड, समयबद्ध भूमि मापी और जनसंवाद कार्यक्रम उसी कड़ी का हिस्सा हैं। इन पहलों का उद्देश्य है कि आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और पारदर्शी तरीके से समस्याओं का समाधान हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। अपने संबोधन में विजय सिन्हा ने जनता से भी अपील की कि वे किसी भी तरह के बिचौलियों या दलालों के झांसे में न आएं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो सीधे प्रशासन और विभाग तक शिकायत पहुंचाएं। सरकार जनता के साथ खड़ी है और किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने दोहराया कि मार्च के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान और तेज होगा। ह्लअब चेतावनी नहीं, कार्रवाई होगी,ह्व उन्होंने कहा। उनके इस सख्त रुख से यह साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में बिहार में भूमि माफियाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

एक नजर

शिवहर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 10 हजार घूस लेते राजस्व कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तार

शिवहर। बिहार में आए दिन घूसखोर पकड़े जा रहे हैं, इसके बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने हम नहीं सुधरेंगे की मानो कसम ही खा ली है। यही कारण है कि निगरानी की कार्रवाई के बावजूद ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बिहार के शिवहर जिले से सामने आई है जहां विजिलेंस की टीम ने एक और घूसखोर को दस हजार रुपए घूस लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। शिवहर जिले में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुरनहिया अंचल के राजस्व कर्मचारी रामकृत महतो को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारी को 10 हजार रुपये घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। जानकारी के अनुसार, राजस्व कर्मचारी दाखिल-खारिज के काम के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

बिहार में अवैध खनन पर सख्ती, एक महीने में 4,582 जगह छापे, 574 वाहन जब्त

पटना। बिहार सरकार ने अवैध बालू और पत्थर खनन के खिलाफ अपना रुख और सख्त करते हुए दिसंबर माह में व्यापक अभियान चलाया। खान एवं भूतत्व विभाग ने पूरे राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध 4,582 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 574 वाहन जब्त किए गए और 248 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। विभाग के अनुसार, औरंगाबाद जिले में सर्वाधिक 331 छापे मारे गए, जबकि अवैध खनन से जुड़े मामलों में सबसे अधिक 15 गिरफ्तारियां पटना जिले में हुईं। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध खनन की जड़ों पर प्रहार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा और सख्त निगरानी का असर राजस्व संग्रह पर भी साफ दिख रहा है। दिसंबर 2025 तक विभाग ने अपने वार्षिक राजस्व लक्ष्य की तुलना में 102 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल कर ली है। अधिकारियों के मुताबिक, अवैध खनन पर नियंत्रण और वैध खनन को बढ़ावा देने से ही राजस्व में यह उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों से लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिलेंगी, वहां केवल खनन माफिया ही नहीं, बल्कि संबंधित प्रशासनिक इकाइयों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। सभी जिलों के खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायत मिलते ही त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कपड़ा दुकानदार के अकाउंट से 42 लाख किया साइबर ठगों से गायब

सासाराम। साइबर फ्रॉड का शिकार बनने के बाद एक व्यक्ति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जाता है कि 42 लाख रुपए उसके खाते में लोन के नाम पर भेजा गया फिर कुछ देर बाद उस रकम को उड़ा लिया गया। जिससे आहत होकर सासाराम के दरीगांव थाना क्षेत्र के खैरा गांव का रहने वाले अरुण कुमार सिंह ने अपने ही घर में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना सामने आने पर इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक अरुण कुमार सिंह ने साइबर फ्रॉड से संबंधित आवेदन दो दिन पहले ही रोहतास के एसपी रौशन कुमार को दिया था। आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं होता देख अरुण ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बता दे कि करपुरवा में अरुण कुमार सिंह एक छोटा सा साड़ी का दुकान चलाते थे। उसी दुकान में पूंजी के लिए जेनिथ फाइनेंस नामक एक संस्था से वह संपर्क में आए। उसके द्वारा बंधन बैंक में एक अकाउंट खुलवाया गया।

बेतिया राज की जमीन को खाली करने का आदेश, 355 परिवारों को नोटिस जारी

एजेंसी। पटना

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया राज की जमीन पर बसे सैकड़ों परिवार अब अपने घर छोड़ने के कगार पर हैं। भितहा प्रखंड में बेतिया राज की भूमि पर बसे साढ़े तीन सौ (355) परिवारों को हटाने की तैयारी की जा रही है। अंचल प्रशासन ने बेतिया राज प्रबंधक के निर्देश के तहत 355 लोगों को नोटिस जारी कर आवासीय जमीन खाली करने को कहा है। नोटिस मिलने के बाद से ही लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वजों को बेतिया राज से जमीन मिली थी और वे इस इलाके में 125 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई बार बाढ़ और आग जैसी घटनाओं के कारण उनके पुराने कागजात नष्ट हो गए। अब अंचल प्रशासन इन कागजातों की मांग कर रहा है, जबकि इतने पुराने दस्तावेजों का उपलब्ध न होना

स्वाभाविक है। कागजात न होने के कारण अब घर उजड़ने की नौबत आ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे उनका जीवन और घर-गृहस्थी बर्बाद हो जाएगा और जीवनभर बसाया घर टूट जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने जीवनभर की पूंजी लगाकर घर बनाया है और अब अगर कार्रवाई हुई तो उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा। ग्रामीण लीज या नए नीलामी के जरिए जमीन देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे गरीब और मजदूर हैं, और उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने सरकार और बेतिया राज प्रबंधक से सहानुभूति बरतने की अपील की है। भितहा के सीओ मनोरंजन शुक्ला ने कहा कि ग्रामीणों पर सहानुभूति या किसी कार्रवाई का निर्णय पूरी तरह बेतिया राज प्रबंधक पर निर्भर है और आंचल प्रशासन उनके निदेर्शानुसार कार्रवाई कर रहा है।

मुजफ्फरपुर में 18 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या कर्ज और गरीबी के तनाव में उठाया आत्मघाती कदम

एजेंसी। पटना

मुजफ्फरपुर जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर (वार्ड संख्या 10) में एक 18 वर्षीय युवक ने फंदे से लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। मृतक की पहचान हरदी मेला निवासी ओम प्रकाश साह के पुत्र कृष्णा के रूप में की गई है। इस घटना के बाद परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। मृतक के पिता ओम प्रकाश साह ने बताया कि उनका बेटा पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में था। गरीबी के कारण घर की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते कृष्णा अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ-साथ एक स्थानीय किराना दुकान में काम भी करता था। परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था, जिसे लेकर कृष्णा अक्सर परेशान रहता था। इसी आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव ने अंततः उसे यह खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सदर थाना पुलिस दलबल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए मुजफ्फरपुर से एफएसएल (ऋछ) की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने कमरे की बारीकी से जांच की और साक्ष्य संकलित किए हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है। घटना की खबर मिलते ही इलाके के मुखिया प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और प्रशासन से उचित मदद की मांग की।

मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स के बकायेदारों को चेतावनी, तीन करोड़ 66 लाख का बकाया भुगतान करने का नोटिस जारी

एजेंसी। पटना

पटना स्थित मशहूर मौयालोक कॉम्प्लेक्स में नगर निगम ने लंबे समय से बकाया रखरखाव चार्ज और ग्राउंड रेंट न चुकाने वाले दुकानदारों और कार्यालयों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। रविवार को हुई समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कॉम्प्लेक्स के कुल 278 दुकानों और कार्यालयों पर लगभग 3 करोड़ 66 लाख 15 हजार 4 रुपये का बकाया जमा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना नगर निगम ने संबंधित बकायेदारों को नोटिस जारी किया है और सात दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नगर निगम के अनुसार, बकायेदार अपनी राशि ऑनलाइन निगम की वेबसाइट के माध्यम से या सीधे कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयावधि में भुगतान न

करने की स्थिति में निगम किसी भी समय बिजली और जलापूर्ति कनेक्शन काटने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस कार्रवाई के संबंध में कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी और बकायेदारों को किसी भी परिस्थिति में राहत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बकायेदारों के खिलाफ विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों और कार्यालय स्वामियों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान कर अनावश्यक कार्रवाई से बचें। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नगर निगम की अपनी जन्म-मृत्यु शाखा भी मौयालोक कॉम्प्लेक्स में आवंटित कार्यालय का मेंटेनेंस और ग्राउंड रेंट भुगतान नहीं कर रही है। रिकॉर्ड के अनुसार जन्म-मृत्यु शाखा पर लगभग 4.46 लाख रुपये का बकाया है।

बिहार के 19 जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

अगले दो दिनों में बढ़ेगी ठंड

एजेंसी। पटना

बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। बिहार के कई जिलों में अधिकतम तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को दिन में भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अगले 24 घंटे के लिए उत्तर और मध्य बिहार के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में शीत दिवस और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में दृश्यता बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। पिछले 24 घंटे में गयाजी सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वहीं सीवान और नालंदा का 5.6 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का छह डिग्री सेल्सियस, रोहतास का 7.2 डिग्री सेल्सियस, सारण का 7.3 डिग्री सेल्सियस, अरवल का 7.5 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया का 10 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य में अधिकतम तापमान 13.4 से 19.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में दर्ज किया गया। वहीं ठंड ने रात में ज्यादा असर दिखाया।

कोहरे ने बढ़ाई परेशानी

ठंड के साथ-साथ कोहरे का असर भी बढ़ गया है। राज्य के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। सबसे कम दृश्यता वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में दर्ज की गई, जहां दृश्यता महज 50 मीटर तक सिमट गई। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर भी असर देखने को मिला।

अगले दिनों में और बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इससे प्रदेश में ठंड और बढ़ने के आसार हैं।

गंडक नदी में दिखा विशाल अजगर, वन विभाग ने भारी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू

एजेंसी। पटना

वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गंडक नदी के रमदौली घाट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर के दिखने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और उसे देखकर लोग हैरान रह गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अजगर की लंबाई करीब 15 से 16 फीट थी और वह काफी वजनदार था। रेस्क्यू के दौरान टीम ने बेहद सावधानी बरती ताकि अजगर को किसी तरह की चोट न पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंडक नदी में उन्होंने पहली बार इतना बड़ा अजगर देखा है, हालांकि इस नदी क्षेत्र में अक्सर वन्य जीव दिखाई देते रहते हैं। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग की टीम ने चारों ओर घेराबंदी कर लोगों को अजगर के पास जाने से रोका और जंगली जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विशेष उपकरणों की मदद से अजगर को सुरक्षित रूप से काबू में कर लिया गया। इसके बाद वन विभाग की गाड़ी से उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में ले जाकर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया।